

प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला

08.09.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

मुख्य समाचार

- मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को देहरा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश।
- राज्य में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य करेगी सरकार।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा— भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार—2025 के लिए 15 सितम्बर तक दाखिल होंगे नामांकन।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को देहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज देहरा क्षेत्र का दौरा किया और कहा कि क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विकास परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए ज़रूरी औपचारिकताएं निर्धारित समय में पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा ज़िला को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देहरा में भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने देहरा के बनखंडी में बन रहे जूलोजिकल पार्क के कार्य में तेजी लाने के साथ-साथ पौंग डैम के आस-पास पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने देहरा में पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने वाले संभावित स्थलों को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए।

उद्योग मंत्री

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि सीमित संसाधन होने के बावजूद भी प्रदेश सरकार जनहित कार्य में कोई कमी नहीं आने दे रही है। नाहन में आज जनसमस्याओं व मांगों को सुनने के अवसर पर उन्होंने ये बात कही। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि गत वर्ष व हाल ही में प्रदेश में आई आपदाओं के कारण हुई क्षति की भरपाई करने के साथ-साथ विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया और आम लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक सौ 50 करोड़ रुपए की हिम-उन्नति योजना चलाई जा रही है। उद्योग

मंत्री ने जन समस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया और शेष समस्याओं के अधिकारियों के निपटारे के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य किया जाएगा। वे आज शिमला में राज्य ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा “नशे के संकट से युवाओं को बचाओ” विषय पर आयोजित अधिवेशन में बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में सिंथेटिक ड्रग में तेजी से वृद्धि हुई है जो चिंता का विषय है और इस मुद्दे को जल्द ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते नशे के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कानून में भी प्रभावी बदलाव लाने की ज़रूरत है, और इस दिशा में भी विचार किया जाएगा। इस अधिवेशन में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने नशाखोरी की रोकथाम विषय पर अपने विचार साझा किए।

विक्रमादित्य सिंह

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार भांग की खेती को वैध करने की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार इस संबंध में बिल लाने के पक्ष में है। शिमला ज़िले के मूलबरी देवनगर में आज एक खेल प्रतियोगिता के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि भांग का इस्तेमाल दवाईयों में होता है और इसके अलावा कपड़ा बनाने के साथ-साथ भांग से कई अन्य उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर हिमाचल की दिशा में आय के संसाधनों को विकसित कर रही है, और इसी कड़ी में कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं।

जयराम ठाकुर

विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह है। मनाली में आज सदस्यता अभियान के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने प्रदेश में 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के प्रयासों से इस लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस सरकार को घेरते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार केवल केन्द्र के ऊपर आश्रित रह गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश पर ऋण 90 हजार करोड़ रूपए तक पहुंच गया है जो आगामी दिसम्बर माह तक एक लाख करोड़ रूपए से अधिक हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने जो ऋण 5 वर्ष में लिया था, उसे मौजूदा सरकार केवल 20 महीने के कार्यकाल में ही ले चुकी है। जयराम ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोज़गार देने में भी विफल रही है।

बाली

प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आर.एस. बाली ने कहा है कि राज्य सरकार हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण व संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत प्रदेश में

होने वाले विभिन्न मेलों व उत्सवों को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शिमला ज़िले में ठियोग के देवरीघाट में एक मेले के शुभारम्भ पर उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों ने अपनी समृद्ध संस्कृति व कलाओं को जीवित रखा है और नई पीढ़ी भी इस दिशा में प्रयासरत है। बाली ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को प्रत्येक ज़िले में देव परंपरा संस्कृति की एक-एक कॉफी टेबल बुक और फोटो गैलरी बनाकर विभाग के सभी होटलों में स्थापित करने के निर्देश दिए।

खेल मंत्री

केन्द्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत 2030 के यूथ ओलिंपिक और 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलिंपिक खेलों की मेजबानी के लिए दावेदारी पेश करेगा। वे आज नई दिल्ली में एशिया ओलिंपिक परिषद की 44वीं महासभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने खेल बजट को 2014-15 के लगभग एक सौ 43 मिलियन डॉलर से बढ़ाकर वर्तमान में लगभग 4 सौ 70 मिलियन डॉलर कर दिया है। खेल मंत्री ने कहा कि इस सहायता ने एशियाई खेलों में एक सौ 7 पदक और एशियाई पैरा खेलों में एक सौ 11 पदक के साथ देश के असाधारण खेल प्रदर्शन में काफी योगदान दिया है।

पुरस्कार

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन 15 सितंबर तक किए जा सकेंगे। महिला व बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों के संकल्प, क्षमता और उत्साह को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है।

स्कूल

शिमला ज़िले के सौ स्कूलों को अधिकारियों ने राज्य सरकार की “अपना विद्यालय-द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम” के तहत गोद लिया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत अधिकारी को संबंधित स्कूल में महीने में एक बार जाना अनिवार्य किया गया है। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि इस दौरान अधिकारी बच्चों के साथ परस्पर संवाद करेंगे और उनके साथ अनुभव व जीवन मूल्यों को लेकर विचार-विमर्श करेंगे। इसके अलावा अधिकारी स्कूल स्टाफ व एस.एम.सी. के साथ बैठक कर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सुझाव भी दे सकेंगे।

मार्ग बहाल

किन्नौर ज़िले के निगुलसरी क्षेत्र में अवरूद्ध हुआ राष्ट्रीय उच्च मार्ग-5 सभी प्रकार के वाहनों के लिए बहाल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से निगुलसरी में बार-बार भूस्खलन होने के कारण लोगों को

तरांडा गांव होते हुए करीब 2 घंटे का पैदल सफर तय करने को मजबूर होना पड़ रहा है। किन्नौर ज़िला सहित स्पीति क्षेत्र को जोड़ने वाला ये एकमात्र मार्ग है और इस मार्ग के बार-बार अवरुद्ध होने से किसानों व बागवानों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज शाम मार्ग बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इस क्षेत्र में हर समय भूस्खलन का खतरा बना रहता है, ऐसे में प्रशासन ने इस मार्ग पर सफर करते समय लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।

सीपीएस

मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू ज़िले में मलाणा मार्ग सहित मलाणा डैम वन तक का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस आपदा प्रभावित क्षेत्र में एक स्पेन तैयार हो चुका है और 20 सितम्बर तक दूसरा स्पेन तार भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सड़क के पुनर्निर्माण में अभी कुछ समय लगेगा, तब तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए तार स्पेन की मदद से काफी अधिक सुविधा मिलेगी। मुख्य संसदीय सचिव ने बलाधी गांव में पानी की समस्या को लेकर भी ग्रामीणों से बातचीत की और विभाग को पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को देहरा क्षेत्र में विकास कार्यों में तेज़ी लाने के लिए निर्देश।
- राज्य में नशाखोरी की समस्या से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति के साथ कार्य करेगी सरकार।
- विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा— भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह।
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार—2025 के लिए 15 सितम्बर तक दाखिल होंगे नामांकन।

.....